कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QSDl : +91(11) 23387887
पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी-36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक - प्रभात झा

विषय-सूची

शपथ-ग्रहण समारोह

भाजपा-नीत एनडीए सरकार ने की नए युग की शुरूआत...................... 7
सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रण-एक प्रभावशाली राजनयिक प्रयास...... 9

विशेष

सुमित्रा महाजन बनीं लोकसभाध्यक्ष.. 14

लेख

जश्न ही नहीं, चुनौतियां भी सामने हैं!
- **अरुण जेटली**... 10
हैरान करती मजबूरी
- **बलबीर पुंज**... 11
धारा : 370 - राष्ट्रपति चाहें तब खत्म कर दें
- **सुब्रमण्यम स्वामी**... 13
रचनात्मक विपक्ष का अभाव
- **हृदयनारायण दीक्षित**... 19
किसानों और वंचितों की आवाज थे मुंडे
- **तरुण विजय**.. 21
कालाधन पर पहली बार ऐसे तेवर
- **जोगिन्दर सिंह**... 22
दलित राजनीति की नई दिशा
- **डॉ. उदित राज**.. 24

श्रद्धांजलि

गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे.. 26
ताराकांत झा का निधन... 29
नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री तपन सिकदर... 29

नमन!

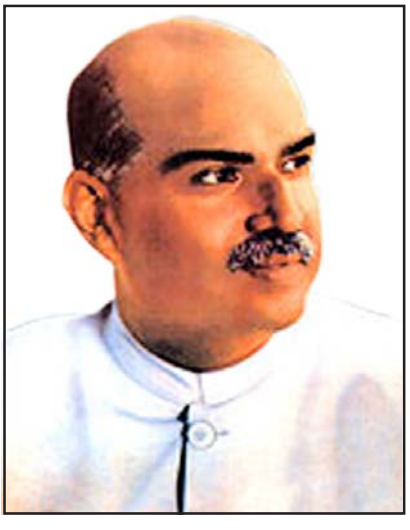

प्रखर राष्ट्रवाद के अग्रदूत

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी

के बलिदान दिवस (23 जून) पर उन्हें शत-शत नमन!

बोध कथा

एक नारे का जन्म

यह घटना उस समय की है, जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोर पकड़ रहा था। उधर अंग्रेज प्रथम विश्वयुद्ध में फंसे थे। मुंबई के गवर्नर लार्ड विलिंग्डन ने इस जंग में भारतीयों से सहायता के लिए 'युद्ध परिषद' का आयोजन किया। उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी आमंत्रित किया गया। गवर्नर को आशा थी कि तिलक भी अन्य भारतीय नेताओं की तरह अंग्रेजों को विश्वयुद्ध में हरसंभव मदद देने का वचन देंगे।

तिलक मंच पर आए। उन्होंने भाषण प्रारंभ किया, 'किसी भी बाहरी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए हम भारतीय सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे किंतु 'स्वराज' तथा 'स्वदेश रक्षा' के प्रश्न पर सरकार को भी स्पष्ट वचन देना चाहिए।' 'स्वराज' शब्द सुनते ही विलिंग्डन का चेहरा तमतमा उठा। वे अपने स्थान से उठे और बोले, 'यहां राजनीतिक चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। आप हमारी सहायता का आश्वासन दीजिए और बोलिए कि आप हमारे साथ हैं।' इस पर तिलक ने कहा, 'गवर्नर महोदय, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और यदि आप इस शब्द को सुनने को तैयार नहीं हैं तो मुझ जैसा स्वाभिमानी भारतीय यहां एक क्षण भी उपस्थित नहीं रह सकता।' तिलक की बेबाक बातें सुनकर विलिंग्डन दंग रह गए। उन्होंने पूछा, 'क्या आपके दिमाग में हर समय स्वराज ही गूंजता रहता है?' तिलक बोले, 'बिल्कुल! और यह शब्द तब तक मेरे दिलो-दिमाग पर छाया रहेगा जब तक कि मेरे देश को पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता।' कुछ समय बाद तिलक की यह बात 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' एक नारा बन गई, जिसने देशवासियों में जोश भरने और उन्हें एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई।

संकलन : रेनू सैनी

(नवभारत टाइम्स से साभार)

व्यंग्य चित्र

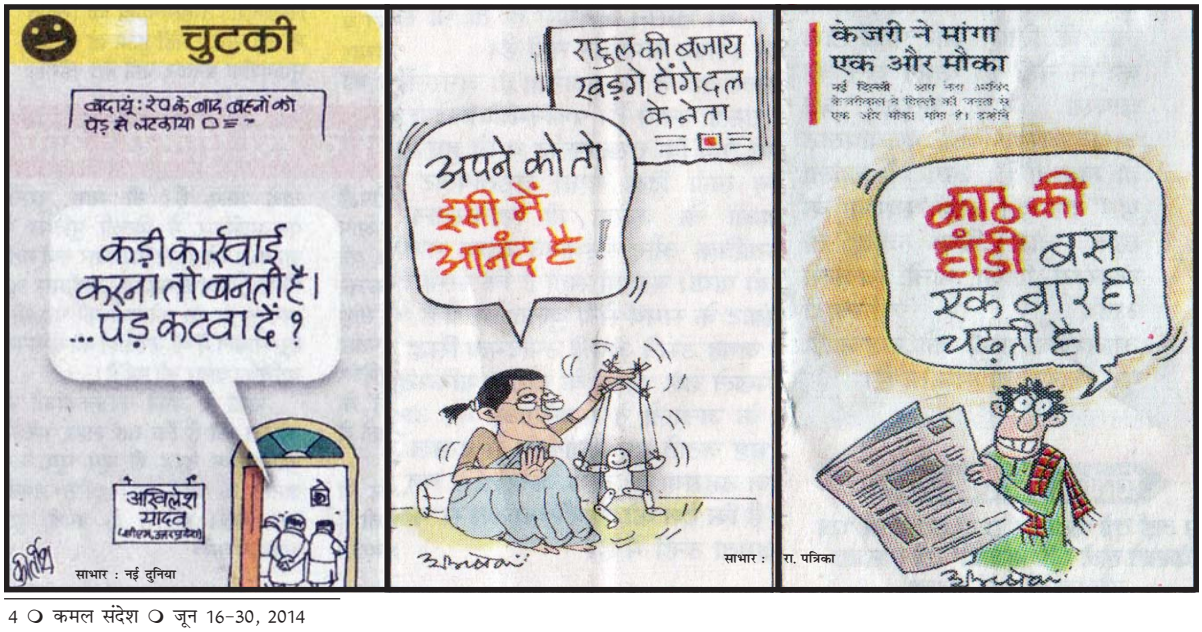

सम्पादकीय

स्पष्ट जनादेश का मतलब जन-आकांक्षाओं की ओर बढ़ें

लोकतंत्र की जान बच गयी। भारत कांग्रेस के शासन से मुक्त हुआ। देश एक परिवार के बंधन से मुक्त हुआ। परिपक्व जनतंत्र ने परिपक्व जनादेश दिया। जनादेश में यह संदेश साफतौर पर परिलक्षित हुआ कि देश की जनता देश के बारे में सोचती है। देश के बारे में देश की जनता सोचना शुरू कर दे, यह सबसे अच्छा संकेत है। देश की जनता ने सोचा, समझा, जांचा, देखा और परखने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी को बहुमत सौंपा। इतिहास रचा गया। दीपक की यात्रा से लेकर कमल की यात्रा में ऐसा दिन अभी तक नहीं आया था। जनता ने राष्ट्रीय विचारधारा के लिए अच्छे दिन ला दिए हैं। देश के लिए अच्छे दिन आए हैं। देश के मन में भी है। देश चाहता भी है कि अच्छे दिन आए।

भाजपा को देश ने पहली बार इतना लोकतांत्रिक प्यार दिया है। भाजपा का इस चुनाव में अखिल भारतीय विस्तार हुआ है। गठबंधन प्रयोग भी सफल रहा। एनडीए को भी बहुमत मिला। देश ने भाजपा को यह कहने का अवसर नहीं दिया कि ''आपने हमें मौका नहीं दिया।'' भरपूर मौका दिया है।

चुनौतियों से भरा समय है। शपथ लेने के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक मिनट गंवाया नहीं है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी आगाह किया है। जनता की अपेक्षाओं से अवगत कराया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनैतिक कूटनीति का लोहा लोगों ने शपथ-समारोह के पहले दिन मान लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह संदेश विश्व भर में गया। उनके कार्य करने की दिशा कैसी होगी, इसकी जानकारी उन्होंने अपने इस कदम से दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 'मां' को एक शॉल भेंट दी। इसके बाद पाकिस्तान से नवाज शरीफ ने मोदीजी की मां के लिए एक साड़ी भेंट की। यहां सवालशॉल और साड़ी का नहीं है, बल्कि बात यहां निकलकर आती है कि 'मां', 'मां' होती है। अपनी मातृभूमि की चर्चा के पहले अपनी 'मां' को याद करना, यह भारतीय संस्कृति की परम्परा है और इसकी शुरूआत कर स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संस्कार का परिचय दिया। पड़ोसी देशों से अच्छे सबंध और भारत अपने पड़ोसी देशों की अगुवाई करने में सक्षम है, यह बात ह्रदय में रखना सामान्य बात नहीं है।

दक्षेस देशों से अच्छे संबंधों की शुरूआत को विश्व ने एक अभिनव पहल माना।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जनता के मन में आशा की अखंड ज्योति जगी है। जनता की आशाओं के अनुरूप मोदी मंत्रिमंडल को खरा उतरना होगा। मोदीजी ने अपने मंत्रिमंडल को भी अनेक बातों से आगाह करते हुए कहा है कि सभी लोग कार्य संस्कृति पर ध्यान देंगे। अधिक परिश्रम करें। मंत्रिमंडल की टीम ने प्रारंभ भी ऐसा ही किया है।

देश समस्याओं के अंबार पर खड़ा है। लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका समाधान नहीं निकाला जा सके। आजादी के सड़सठ साल बाद भारत को जहां पहुंचना चाहिए था, वह वहां नहीं पहुंच सका।

भारत की आशा जगी है। देश के बारे में सोचने वालों की संख्या बढ़ी है। आज आवश्यकता है भारत के बारे में सोचने वालों की। पिछले अनेक वर्षों में देश के बारे में सोचने वालों की कमी रही। देश से जुड़े रक्षा सौदों का मामला हो, देश की सीमाओं का मामला हो, या फिर जम्मू-कश्मीर का मामला हो, मामला चीन से जुड़े सवालों का हो या फिर देश के आन्तरिक मामले हो, हमारी सरकारों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया।

समस्याएं तो रहेंगी लेकिन समस्याओं के निदान के लिए ईमानदारी से प्रयत्न होना चाहिए। आज बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कालाधन जैसी अनेक समस्याएं हैं जो ज्यों की त्यों मुंह बाये खड़ी हैं। इन समस्याओं के लिए ईमानदारी से प्रयत्न होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब इस दिशा में कम से कम ईमानदारी से प्रयास प्रारम्भ होगा।

हमें यह भी ज्ञात है कि वर्षों की समस्याओं का समाधान एक दिन में नहीं होगा, पर प्रयास की दिशा ठीक रही तो लोग उस प्रयास को भी स्वीकार करेंगे। इतना तो लोग कहने लगे हैं कि अब ईमानदार प्रयास के दिन आए हैं।

मुंडेजी किसानों और गरीबों के मसीहा थे

भाजपा महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता एवं नवनियुक्त केन्द्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे का निधन संगठन और सरकार दोनों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। 64 वर्षीय मुंडेजी ने महाराष्ट्र की राजनीति में जनसंघ के दीए से अपनी राजनीति प्रारंभ की थी। वे जमीन से जुड़े और संघर्ष के प्रतीक थे। पार्टी का कार्य उन्होंने सुदूर गांव से शुरू किया था। मराठवाड़ा की पहचान बन चुके मुंडेजी के असामयिक निधन ने सभी देशवासियों को झकझोर दिया। जिला पंचायत से लेकर ग्रामीण विकास मंत्री बनने तक वे महाराष्ट्र में पांच बार विधायक रहे। भाजपा-शिवसेना गठबंधन की सरकार में वे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे। दलितों और पिछड़ों के वे इकलौते लोकप्रिय जननेता थे। 'साहेब' उनके लिए लोकप्रिय संबोधन था।

गोपीनाथजी मुंडे मराठवाड़ा सहित महाराष्ट्र की जनता ही नहीं भाजपा जैसे संगठन को अनाथ छोड़ गए। जननेता एक दिन में नहीं बनता। गत 40 वर्षों का सतत संघर्ष और कार्य की निरंतरता के कारण वे इस शिखर पर पहुंचे थे। दिग्गजों के बीच में अपनी पहचान बनाने वाले गोपीनाथ मुंडेजी के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़ उनकी लोकप्रियता की स्वयं की स्वयं साक्षी बना।

महाराष्ट्र के चुनाव सिर पर थे। संगठन उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र चुनाव की तैयारी कर रहा था, लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। महाराष्ट्र भाजपा में वे रीढ़ की हड्डी थे। सच में मुंडेजी के निधन से भाजपा महाराष्ट्र के रीढ़ की हड्डी टूट गई। धीरे-धीरे गत पांच वर्षों में भाजपा संसदीय दल के उपनेता के रूप में उन्होंने अपनी अखिल भारतीय छवि बनाना शुरू कर दी थी। देश में खासकर महाराष्ट्र में वे शेतकारी (किसान) नेता के रूप में गरीबों के नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में किसानों और गरीबों की लड़ाई जोरदारी से लड़ी। वे महाराष्ट्र की राजधानी में दबंग नेता माने जाते थे। अपनी बात बेबाक कहना उनका स्वभाव था। वर्षों तक शिवसेना के स्व. बालठाकरे से उनके संबंध परिजनों की तरह रहे। उन्होंने महाराष्ट्र की विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में शानदार काम किया। वे जीवन के प्रारंभ से लेकर अपने जीवन के अंत तक जनता के लिए जीवित रहे और उन्हीं के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। जिस दिन सड़क दुर्घटना में दिल्ली में उनकी मौत हुई, वे दिल्ली से अपने चुनाव क्षेत्र बीड़ में आयोजित अभिनंदन समारोह में जा रहे थे। लेकिन विधि कुछ और लिख रहा था। जहां उस दिन अभिनंदन होना था, वही एक दिन बाद उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। ईश्वर की लीला कौन जानता है। अत: ईश्वर के निर्णय को हम सिर झुकाकर नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जननेता को अपने चरणों में उचित स्थान दें। ■

वीर सावरकर के जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को 28 मई को उनके जन्मदिवस पर संसद में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्री मोदी ने ट्वीटर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वीर सावरकर को सदैव एक प्रबुद्ध लेखक, चिंतक, कवि और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र उन्हें भारत के पुनरुद्धार के प्रति किए गए अथाह प्रयासों को याद रखेगा और इसके लिए हम उनको नमन करते हैं।

शपथ-ग्रहण समारोह

भाजपा-नीत एनडीए सरकार ने की नए युग की शुरूआत

गत 16 मई को भाजपा की शानदार जीत हुई, जिसमें भाजपा को 282 सीटें प्राप्त कर पूर्ण बहुमत मिला और एनडीए के अन्य सहयोगियों को साथ मिलाकर यह संख्या 336 बन गई है, इस विजय के बाद श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ-ग्रहण ली, जिसे भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण मे आयोजित समारोह में दिलाई। महामहिम राष्ट्रपति ने श्री मोदी के साथ 23 केबिनेट मंत्रियों, 10 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 12 राज्य मंत्रियों ने शपथ दिलाई। पूरे देश के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर था क्योंकि भाजपा और श्री मोदी जैसी शख्सियत के लिए 1984 के बाद से यह पहला अवसर था जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। यह अवसर भी पहली बार प्राप्त हुआ जिसमें कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए भी, जो बहुत समय से भारतीय राजनीति के इतिहास में अपना प्रभुत्व बनाए हुए थी, उसे इतनी बड़ी करारी हार का सामना कभी नहीं करना पड़ा।

इस ऐतिहासिक अवसर पर, पूरा प्रांगण दर्शकों से परिपूर्ण था जिनमें 3500 से अधिक दिग्गज शामिल थे और इनमें 'सार्क' देशों के शासनाध्यक्ष भी रहे, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ, श्रीलंका के प्रेजीडेण्ट श्री महिंद्रा राजपक्षे, अफगानिस्तान प्रेजीडेण्ट श्री हामिद करजई, नेपाल प्रधानमंत्री श्री सुशील कोइराला, भूटान के प्रधानमंत्री श्री टीशेरिंग तोपमे और मालदीव के राष्ट्रपति श्री अब्दुल्ला यामीन अब्दुल

गयूम शामिल थे।

अन्य दिग्गजों में भारत के उप-राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य महत्वपूर्ण राजनेता शामिल रहे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अन्य अनेक प्रमुख नागरिकों ने भी शपथग्रहण में शामिल होकर जश्न का माहौल बना दिया जिनमें बॉलीवुड के सलमान खान, उनके पिताश्री सलीम खान, ह्रतिक रोशन, विवेक ओबराय, बालीवुड दम्पति अनुपम और किरण खेर, बालीवुड फिल्म निर्माता मधुर भण्डारकर, संगीत निर्देशक बप्पी लाहिरी, पूनम ढिल्लों और कई अनेक अभिनेता- विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमामालिनी और कई उद्योगपति- मुकेश अम्बानी और उनके परिवार के सदस्य, 'टाटा परिवार' और अन्य प्रमुख उद्योगपतियों ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से श्री मोदी को हिन्दी में पद और गोपनीयता की शपथ लेते देखा और लाखों-करोड़ों ने अपने टी.वी. सैटों पर नए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के ऐतिहासिक शपथ-ग्रहण समारोह का आनन्द लिया और उन्हें आशा है कि राष्ट्र के 125 करोड़ लोगों के सपनों और उनकी महत्वाकांक्षाओं को साकार किया जाएगा।

भारतीय राजनीति, मीडिया, मनोरंजन और व्यापार से जुड़ी अनेक हस्तियां भी इस अवसर पर मौजूद थीं। अनेक देशों के शासनाध्यक्षों की उपस्थिति भारत के साथ राजनयिक विजय की प्रतीक बनकर सामने आई हैं। शपथ-ग्रहण समारोह का मोह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि भारत की सीमा के बाहर के देशों में भी देखने को मिला।

कड़ी मेहनत से जीती इस लड़ाई के बाद श्री मोदी ने जाति, धर्म, क्षेत्र और जेण्डर को ध्यान में रखते हुए प्रतिभाशाली, अनुभवी, युवाओं और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी कैबिनेट को संतुलित बनाने की कोशिश की है, जिसकी चर्चा श्री मोदी ने अपने चुनावी प्रचार अभियान में भी की थी।

श्री मोदी को शपथ दिलाने के बाद जिन केबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली, वे हैं- श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू और श्री नितिन गडकरी, पूर्व कर्नाटक मुख्यमंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौडा, पूर्व मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री श्री उमा भारती, राज्यसभा की पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, पूर्व महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री श्री गोपीनाथ मुंडे, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान, पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री श्री कलराज मिश्रा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी, वरिष्ठ टीडीपी नेता श्री अशोक गजपति राजू, शिवसेना नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अनंत गीते, शिरोमणि अकाली दल की सुश्री हरसिमरत कौर बादल, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पूर्व ओडिशा भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय आदिवासी मंत्री श्री जुआल ओरम, बिहार भाजपा एमपी श्री राधामोहन सिंह, पूर्व मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री थावर चंद गहलोत, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती स्मृति ईरानी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष डा. हर्षवर्धन। 38 वर्षीया श्रीमती स्मृति ईरानी, सबसे कम आयु की भाजपा नेता हैं जिन्हें श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी केबिनेट में शामिल किया है।

जिन राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें शामिल हैं- जनरल (रिटायर्ड) श्री विजय कुमार सिंह, गुडगांव एमपी श्री राव इन्द्रजीत सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री संतोष गंगवार, गोवा भाजपा नेता श्री श्रीपद नाइक, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री धर्मेन्द्र प्रधान, असम भाजपा अध्यक्ष श्री सर्वानंद सोनोवाल, भाजपा प्रवक्ता श्री प्रकाश जावड़ेकर, भाजपा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सांसद पीयूष गोयल, जम्मू और काश्मीर भाजपा नेता डा. जीतेन्द्र सिंह, भाजपा प्रवक्ता श्रीमती

निर्मला सीतारमण, कर्नाटक भाजपा नेता श्री जी.एम. सिद्धेश्वरा, गाजीपुर एमपी श्री मनोज सिन्हा, गंगानगर एमपी श्री निहालचंद चौहान, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष श्री उपेन्द्र कुशवाहा, तमिलनाडु, भाजपा अध्यक्ष और कन्याकुमारी एमपी श्री पॉन राधाकृष्णन, अरूणाचल प्रदेश से भाजपा एमपी श्री किरन रिजुजु, फरीदाबाद भाजपा एमपी श्री कृष्णपाल गुज्जर, मुजफरनगर एमपी श्री संजीव बलियान, गुजरात एमपी श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा, महाराष्ट्र भाजपा एमपी श्री राव साहेब दादाराव रान्वे, भाजपा एमपी रायगढ़ (छत्तीसगढ़) श्री विष्णु देव साई और झारखण्ड एमपी श्री सुदर्शन भगत।

इससे पूर्व, श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ-ग्रहण से पूर्व अपनी राजनैतिक जीवन की शुरूआत करने से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। सामान्यतया, प्रधानमंत्री पदभार संभालने के बाद राजघाट पर गांधी मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित किया करते हैं, परन्तु ऐसा पहली बार हो रहा है कि मनोनीत प्रधानमंत्री ने शपथ-ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपिता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी गुजरात भवन से लगभत 7.40 प्रातः गांधी समाधि के लिए रवाना हुए और वहां लगभग 15 मिनट का समय बिताया। उन्होंने समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की

शेष पृष्ठ 14 पर

सार्क देशों के नेताओं को आमंत्रण-एक प्रभावशाली राजनयिक प्रयास

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने शपथ-ग्रहण समारोह में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोआप्रेशन (सार्क) के शासनाध्यक्षों को आमंत्रित कर बड़े प्रभावशाली ढंग से अपने पड़ौसी देशों के साथ राजनयिक प्रयास शुरू कर एक नए युग की शुरूआत की है। ऐसा पहली बार हो रहा है, जब किसी प्रधानमंत्री ने अपने शपथ-ग्रहण समारोह में 'सार्क' देशों को आमंत्रित किया है। इससे यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री

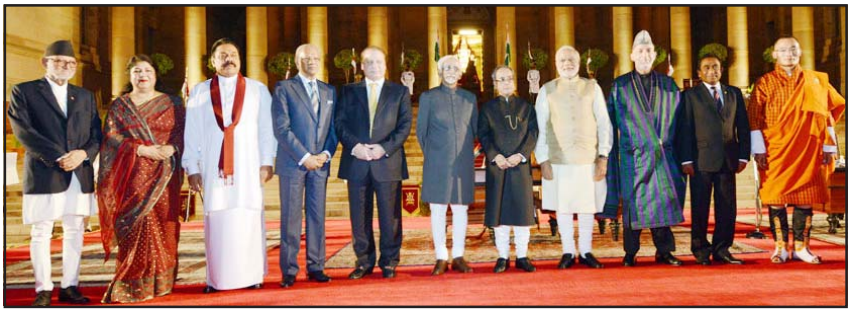

श्री नरेन्द्र मोदी 'सार्क' देशों का एक महत्वपूर्ण ग्रुप बनाना चाहते हैं जिससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावशाली ढंग से अपनाया जा सकता है।

एक पूर्व राजनयिक ने श्री नरेन्द्र मोदी की इस अभूतपूर्व शुरूआत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा भी है कि ''मोदी ने 'सार्क' देशों के नेताओं को आमंत्रित कर पूरे विश्व में एक दृढ़ संदेश देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पाकिस्तान के बारे में इसे एक 'अलग' दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान भी 'सार्क' देशों का एक भाग है। श्री मोदी ने तो अपने चुनाव नारे को सार्थक किया है- 'सबका साथ, सबका विकास' जो 'सार्क' देशों के अलावा और सभी देशों पर भी लागू होता है।

''श्री मोदी ने 'सार्क' देशों जैसे संगठनों में एक नया जीवन प्रदान किया है और यह संदेश दिया है कि सभी 'सार्क' देशों को आपस में मिल कर काम करते हुए विकास, सहसंबंध निर्माण और समृद्धि की आवश्यकता है। बहुत से लोगों ने श्री मोदी के इस प्रयास को नकारात्मक ढंग से चित्रित करने की कोशिश है। इसमें संदेह नहीं कि श्री मोदी ने अपने चुनाव-अभियान के दौरान आक्रामकता बरतते हुए कहा कि पिछले दस वर्षों से जो सत्तारूढ़ पार्टी शासन कर रही है, उसे उखाड़ फेंकने की जरूरत है। सार्क देशों को आमंत्रण एक मास्टरस्ट्रोक था क्योंकि उन्होंने एक ही झटके में यह संदेश दे दिया कि हमें मिलकर इस पूरे क्षेत्र का विकास करना और समृद्ध बनाना है।

विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने 'सार्क' देशों को आमंत्रण भेजने पर कहा है कि मोदी ने जिन आठ- सदस्यीय ब्लॉक के नेताओं को समारोह में आमंत्रण भेजकर सरकार की मंशा साफ कर दी है और हम प्रतिबद्ध हैं कि हम दक्षिण एशिया के देशों के साथ सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण और समावेशी संबंध बनाना चाहते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री 'सार्क' देशों में से प्रत्येक देश के साथ मित्रतापूर्ण सहयोग रखना चाहते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आमंत्रण पहला कदम सिद्ध हुआ है। इन देशों में से प्रत्येक देश के साथ हमारे संबंधों में नई सरकार ने प्रारंभ में ही एक आशाप्रद शुरूआत कर दी है। ■

जश्न ही नहीं, चुनौतियां भी सामने हैं!

✍ अरुण जेटली

पिछले सप्ताह हमारे सामने कई ऐतिहासिक घटनाएं घटीं। एनडीए की चुनावी विजय का शंखनाद अभी तक जारी है। प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों द्वारा शपथ-ग्रहण समारोह सचमुच एक अविस्मरणीय घटना बनी है। शपथ-ग्रहण समारोह में 'सार्क' नेताओं की उपस्थिति स्वयं में एक अनुपमता रखती है। किन्तु, मंत्रियों के कामकाज वितरण ने अहसास कराया है कि हमारे सामने क्या कुछ करने पर ध्यान देना होगा। मेरे लिए, तो पिछला सप्ताह जश्न के साथ ही साथ चुनौतियों से भरपूर रहा है। मुझे दो प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसे देखते हुए और साथ ही आचार संहिता के कारण पैंडिग मुद्दे मेरे लिए प्रमुख चिंता का विषय बने हैं। नि:संदेह मेरे लिए तात्कालिक चुनौती अर्थव्यवस्था की स्थिति है जिस पर हम सबकी निगाहें लगी हुई हैं।

हमें विरासत में जो अर्थव्यवस्था मिली है, उसमें जीडीपी निरन्तर दो वर्षों में 5 प्रतिशत से भी कम रही है। खनन और खदान क्षेत्रों में नकारात्मक विकास की प्रवृत्ति बनी रही है। पिछले वर्ष विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र अत्यंत निराशाजनक रहा है। निवेश-चक्र में भी बाधाएं रही हैं। नकारात्मक रूखों ने व्यापार, होटल और परिवहन क्षेत्रों पर दुष्प्रभाव डाला है जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में विकास की गति अत्यंत धीमी बनी रही है। मई माह में जा सीएसओ के अनुमान के अनुसार मुद्रास्फीति निरन्तर बढ़ती रही है जो अप्रैल में 8.9 प्रतिशत तक पहुंच गई। आर्थिक विकास की धीमी गति के साथ ही साथ उच्च मुद्रास्फीति का दबाव मेक्रो-इकानॉमिक माहौल के लिए एक गहन चुनौती खड़ी कर दी है। कर-संग्रह प्रारम्भिक बजट अनुमानों के अनुसार 10.9 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 10.1 प्रतिशत रह गया है।

हमें विरासत में जो अर्थव्यवस्था मिली है, उसमें जीडीपी निरन्तर दो वर्षों में 5 प्रतिशत से भी कम रही है। खनन और खदान क्षेत्रों में नकारात्मक विकास की प्रवृत्ति बनी रही है। पिछले वर्ष विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र अत्यंत निराशाजनक रहा है। निवेश-चक्र में भी बाधाएं रही हैं। नकारात्मक रूखों ने व्यापार, होटल और परिवहन क्षेत्रों पर दुष्प्रभाव डाला है जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में विकास की गति अत्यंत धीमी बनी रही है।

भारत इस तरह की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके कारण कई प्रकार के गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं क्योंकि धीमी गति के साथ बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। आज हमारे सामने विकास गति के पुनरुद्धार, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और लाभप्रद रोजगार के विकास पैटर्न को फिर से बढ़ाना सबसे बड़ी-प्राथमिकता है। घरेलू कम-लागत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और सुधारों की गति में तेजी लाना बहुत आवश्यक है। कीमतों को स्थिर रखना और विकास बढ़ाना-ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं, परन्तु इसके लिए अलग किस्म की रणनीति अपनानी होगी। एनडीए की विजय और कांग्रेस की चुनावों में करारी हार दो अलग अलग चुनावी रवैय्यों को दर्शाता है। पिछली सरकार से लोग बुरी तरह से असंतोष का अनुभव कर रहे थे। श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा/एनडीए से लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। यही वह उम्मीद है जो हमें वर्तमान आर्थिक स्थिति से उबारने को प्रेरित करती है। इसके लिए राजकोषीय ईमानदारी आवश्यक होगी क्योंकि इसमें मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों का सम्मिश्रण करना होगा। धीमी जीडीपी विकास का मतलब 'लोअर टैक्स बॉयंसी' और उच्च राजकोषीय घाटे से है। हमें राजकोषीय अनुशासन के युग की तरफ बढ़ना होगा, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सके और हम अपनी विकास दर बढ़ा सकें। भारत को इसके लिए तैयार करना ही होगा। हमें इस अनुशासन के प्रति वचनबद्ध होना पड़ेगा ताकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकें जिससे प्रत्येक भारतीय का जीवन स्तर सुधरेगा और अपवंचित वर्गों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकेगा। अल्पावधि-अनुशासन का आश्रय लेकर वर्तमान प्रवृत्तियों को उलटा करना होगा जो हमें दीर्घावधि में लाभ पहुंचाएंगी। ■

(लेखक केन्द्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री हैं)

हैरान करती मजबूरी

बलबीर पुंज

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुच्छेद 370 पर दिए बयान के बाद पूरे देश में इस पर बहस चल रही है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने धमकी दी है कि या तो अनुच्छेद 370 रहेगा या जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। इसका क्या निहितार्थ है? क्या जम्मू-कश्मीर किसी परिवार विशेष की निजी जागीर है? संविधान सभा में जम्मू-कश्मीर को दिए जा रहे विशेष दर्जे पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। उसके जवाब में पं. नेहरू द्वारा बिना मंत्रालय के मंत्री बनाए गए प्रशासनिक अधिकारी गोपाल स्वामी आयंगर, जिन्हें जम्मू-कश्मीर के विलय का काम सौंपा गया था, ने यह स्पष्ट किया था कि युद्ध और बगावत के हालात होने के कारण ऐसी 'अस्थायी व्यवस्था' की जा रही है।

अनुच्छेद का शीर्षक-'जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में अस्थायी प्रावधान' भी इसकी पुष्टि करता है। ऐसे में इस अनुच्छेद को शाश्वत बनाए रखने की क्या मजबूरी है?

अनुच्छेद 370 को हटाने पर हो रहे विरोध को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। देश के विभाजन के दौरान देशी रियासतों को भौगोलिक आधार पर भारत या पाकिस्तान में विलय करने की छूट थी। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर, 1947 को पत्र लिखकर भारत में विलय की स्वीकृति दे दी थी। भारत में जो भी रजवाड़े मिले उनके क्षेत्रों को वही संवैधानिक दर्जा मिला जो भारतीय गणराज्य के अन्य राज्यों को मिला था। उनके नागरिकों को वही अधिकार मिले जो अन्य राज्य के नागरिकों को मिले थे, किंतु जम्मू-कश्मीर के मामले में जवाहर लाल नेहरू के अधीन तत्कालीन सत्ता अधिष्ठान ने अदूरदर्शिता बरती। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 565 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। जूनागढ़ का नवाब जन-विद्रोह के कारण स्वयं पाकिस्तान भाग गया था। किंतु महाराजा हरि सिंह के साथ व्यक्तिगत वैरशोधन के लिए नेहरू ने शेख अब्दुल्ला का साथ देने की गलती की। विलय पर महाराजा की सहमति मिल जाने के बावजूद केंद्र हस्तक्षेप करने में हीलाहवाली करता रहा।

हैदराबाद के नवाब को जमीन पर लाने वाले सरदार पटेल के हाथ से कश्मीर मसला छीनकर नेहरू ने अपने पास रख लिया। आज भी कश्मीर में अलगाववाद है तो इसमें अनुच्छेद 370 का बड़ा योगदान है। भारत के रक्तरंजित विभाजन के ठीक बाद 22 अक्टूबर, 1947 को कबीलाइयों के वेष में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू-कश्मीर रियासत पर आक्रमण कर दिया था। रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य सहायता की अपील की।

भारतीय सेना दुश्मनों को परास्त करती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक 1 जनवरी, 1949 को नेहरू ने इकतरफा युद्धबंदी की घोषणा कर दी। जम्मू-कश्मीर के जो हिस्से पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी वाले क्षेत्र में रह गए, उन पर आज पाकिस्तान का कब्जा है और वहां भारत को लहूलुहान करने के लिए जिहादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। बाद में जम्मू-कश्मीर का मसला नेहरू संयुक्त राष्ट्र में ले गए, जहां वह आज भी लंबित है।

जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद नेहरू ने राज्य की कमान शेख

जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद नेहरू ने राज्य की कमान शेख अब्दुल्ला को सौंप दी, जो खुद को 'सदरे रियासत' घोषित कर अपनी महत्वाकांक्षा सींचने लगे। वे विशेष राज्य का दर्जा और 'दो प्रधान, दो विधान और दो निशान' के लिए नेहरू पर दबाव डालने लगे। लंबी बहस के बाद जो सहमति बनी उसे दिल्ली समझौता कहा गया। इसके अंतर्गत अवशिष्ट और समवर्ती शक्तियां राज्य के अधीन रहीं, विशेष नागरिकता अधिकार राज्य का अधिकार बना रहा। राष्ट्रीय तिरंगे के साथ एक अलग झंडा फहराने की अनुमति दी गई। इन व्यवस्थाओं के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का समावेश किया गया।

अब्दुल्ला को सौंप दी, जो खुद को 'सदरे रियासत' घोषित कर अपनी महत्वाकांक्षा सींचने लगे। वे विशेष राज्य का दर्जा और 'दो प्रधान, दो विधान और दो निशान' के लिए नेहरू पर दबाव डालने लगे। लंबी बहस के बाद जो सहमति बनी उसे दिल्ली समझौता कहा गया। इसके अंतर्गत अवशिष्ट और समवर्ती शक्तियां राज्य के अधीन रहीं, विशेष नागरिकता अधिकार राज्य का अधिकार बना रहा। राष्ट्रीय तिरंगे के साथ एक अलग झंडा फहराने की अनुमति दी गई। इन व्यवस्थाओं के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का समावेश किया गया।

अनुच्छेद 370 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि रक्षा, विदेशी व संचार मामलों के अलावा संघ व समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर भारतीय संसद राज्य सरकार की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकती है। भारतीय गणराज्य के स्वरूप पर आघात करने वाले इस प्रावधान का जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कड़ा विरोध किया था। 7 अगस्त, 1952 को डॉ. मुखर्जी ने कहा था, ''आप जो करने जा रहे हैं वह भारत को विखंडित कर देगा। यह उन लोगों को मजबूत कर सकता है जो यह विश्वास करते हैं कि भारत एक देश नहीं, बल्कि भिन्न राष्ट्रों का समूह है।'' जम्मू-कश्मीर में प्रवेश के लिए तब परमिट लेना पड़ता था। देश की अस्मिता व संप्रभुता के साथ हो रहे खिलवाड़ का प्रतिकार करने के लिए डॉ. मुखर्जी ने बिना परमिट के जम्मू जाने का निर्णय लिया। डॉ. मुखर्जी 11 मई, 1953 को जम्मू की सीमा में स्थित रावी के पुल पर पहुंचे तो कठुआ के पुलिस सुपरिंटेंड ने उन्हें राज्य की सीमा में न घुसने का आदेश दिया। डॉक्टर साहब ने इसे मानने से इन्कार कर दिया, जिस पर उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। नजरबंदी के 43वें दिन अर्थात् 23 जून, 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। डॉ. मुखर्जी की शहादत आज भी एक रहस्य है। डॉ. मुखर्जी के बलिदान के बाद 'दो प्रधान, दो निशान' विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत समाप्त हो गए, किंतु अनुच्छेद 370 के माध्यम से 'दो विधान' अब भी कायम है। भारत के नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में कई वर्षो तक रहने के बावजूद यह अधिकार नहीं है कि वे वहां के स्थायी निवासी बन सकें और वहां जमीन या मकान खरीद सकें। उन्हें राज्य विधानसभा, स्थानीय या पंचायत के चुनावों में मतदान करने का अधिकार नहीं है। वहीं जम्मू-कश्मीर के नागरिक को देश के किसी भी भाग में बसने और कारोबार की छूट है। जम्मू-कश्मीर में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 360 वहां लागू नहीं होती। धारा 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं करने वाली राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार है। जम्मू-कश्मीर के मामले में राष्ट्रपति संवैधानिक संकट में भी राज्य में हस्तक्षेप करने के अधिकारी नहीं हैं।

सन 1956 में भारत सरकार ने संविधान में सातवां संशोधन कर जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न अंग बना लिया था। नेशनल कांफ्रेंस की कुटिल मंशा इसे निरस्त कराने की है। इसके समाप्त होते ही राष्ट्रपति के सभी अध्यादेश, संवैधानिक संशोधन, संसद के अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का नियंत्रण अपने आप समाप्त हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य में संघ का शासन लागू करे। वास्तव में अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में कश्मीर घाटी के अलगाववादी मुखर हैं, जिन्हें पाकिस्तान का प्रश्रय प्राप्त है। जम्मू और लद्दाख के लोग इसे अविलंब निरस्त करने के पक्षधर हैं। अनुच्छेद 370 को हटाए बिना कश्मीरी पंडितों की घर वापसी संभव नहीं है। देश की जनता जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा में शामिल करने की हिमायती है। अनुच्छेद 370 का हटना देशहित में है, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ने के साथ राज्य का समेकित विकास संभव है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

(साभार- दै. जागरण)

भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य में संघ का शासन लागू करे। वास्तव में अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में कश्मीर घाटी के अलगाववादी मुखर हैं, जिन्हें पाकिस्तान का प्रश्रय प्राप्त है। जम्मू और लद्दाख के लोग इसे अविलंब निरस्त करने के पक्षधर हैं। अनुच्छेद 370 को हटाए बिना कश्मीरी पंडितों की घर वापसी संभव नहीं है। देश की जनता जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा में शामिल करने की हिमायती है। अनुच्छेद 370 का हटना देशहित में है, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ने के साथ राज्य का समेकित विकास संभव है।

राष्ट्रपति चाहें तब खत्म कर दें

✍ सुब्रमण्यम स्वामी

जब जवाहर लाल नेहरू और माउंट बेटन ने जम्मू-कश्मीर के राजा हरिसिंह को स्वायतत्ता का आश्वासन दिया, तब उन्होंने किसी से सलाह नहीं की थी। न ही तत्कालीन केबिनेट से सलाह ली गई थी। राजा हरिसिंह को आश्वासन दिया गया कि अनुच्छेद-370 के जरिए उन्हें पूर्ण स्वायतत्ता रहेगी। लेकिन संविधान सभा में इसे लेकर सहमति नहीं थी।

इसलिए पं. नेहरू ने सरदार पटेल से आग्रह कर और आत्मसम्मान का हवाला देकर 370 का प्रावधान करवा लिया। हालांकि पटेल ने कहा था कि अनुच्छेद-370 बहुत दिनों के लिए नहीं है। यह एक अस्थायी प्रावधान है। जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने के लिए बनी समिति ज्यों ही अपना काम पूरा कर लेगी, इसे समाप्त कर दिया जाएगा।

भारतीय संविधान में भी 370 को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है। यह अस्थायी प्रावधान 64 साल चल गया है। आगे जरूरत नहीं है, बल्कि इतने साल के बाद यह तो स्थायी-सा ही हो गया। इसे रद्द करने के लिए संसद में वोट की जरूरत नहीं है।

सिर्फ हमारे राष्ट्रपति एक विज्ञप्ति निकाल दें कि यह रद्द की जा रही है तो स्वत: रद्द हो जाएगी। राष्ट्रपति को ऐसी विज्ञप्ति जारी करने के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव मिलना चाहिए। उस समय जम्मू-कश्मीर के लिए बनी संविधान समिति को जम्मू कश्मीर के संविधान की धाराएं और विलय सम्बन्धी धाराएं तय करनी थीं।

उस समय कहा गया कि अगर बीच में कभी 370 को हटाना है तो इस समिति की अनुमति लेनी होगी। लेकिन उसका काम पूरा होने पर 1953 में इस संविधान समिति का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ऐसे में अब सिर्फ यह शेष रह गया कि राष्ट्रपति स्वयं ही विज्ञप्ति जारी कर अनुच्छेद-370 को हटा दें।

अब सवाल है कि इसको रद्द करना है या नहीं? इसका जवाब यह है कि एक देश में दो विधान नहीं हो सकते, इस लिहाज से 370 की कोई जरूरत नहीं है। एक अस्थायी प्रावधान चिरस्थायी नहीं हो सकता। इसे रद्द करना स्वाभाविक-सी बात है। दरअसल, 370 को राजनीतिक हथियार बना लिया गया। कश्मीर में पृथकतावादी चेतना का मूल कारण यही है। हालांकि अलग-अलग बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों की जमात इसके पक्ष-विपक्ष में तर्क देती रहती है। यह जाहिर है कि इससे जनता को कोई फायदा नहीं हुआ है।

कश्मीर में बाकी हिंदुस्तान के लोग न तो निवास बना सकते हैं, न कोई फैक्ट्री-धंधा लगा सकते हैं। इस कारण से वहां रोजगार सृजन भी नहीं हुआ है। इसलिए नुकसान तो हुआ है। अनु. 370 का गलत पक्ष यह भी है कि कश्मीर के लोग तो शेष हिंदुस्तान में बस सकते हैं लेकिन शेष हिंदुस्तानी वहां ऐसा नहीं कर सकते। जब अनु. 370 अस्तित्व में आया था तो नेहरू ने तर्क दिया था कि वहां हिंदू-मुस्लमानों का अनुपात न बदल जाए, इसलिए इसमें शेष हिंदुस्तानियों के न बसने का प्रावधान रखा गया है।

पं. नेहरू ने सरदार पटेल से आग्रह कर और आत्मसम्मान का हवाला देकर 370 का प्रावधान करवा लिया। हालांकि पटेल ने कहा था कि अनुच्छेद-370 बहुत दिनों के लिए नहीं है। यह एक अस्थायी प्रावधान है। जम्मू कश्मीर का संविधान बनाने के लिए बनी समिति ज्यों ही अपना काम पूरा कर लेगी, इसे समाप्त कर दिया जाएगा।

जब आतंककारियों ने पांच लाख कश्मीरी पंडितों को घाटी से खदेड़ा तो अनुच्छेद 370 इसे नहीं रोक पाया। नेहरू का तर्क फीका साबित हुआ। क्या एक तरफ से ही लोग नहीं आ सकते? पूर्वी पाकिस्तान से मुस्लिम आए वो तो भारत के नागरिक बन सकते हैं लेकिन बाकी हिंदुस्तान से लोग जम्मू-कश्मीर में नहीं बस सकते। यह हमारी अखंडता के खिलाफ है। ■

(साभार- अमर उजाला)

सुमित्रा महाजन बनीं लोकसभाध्यक्ष

लगातार आठ बार संसदीय चुनाव जीतीं इंदौर की सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन को सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। सभी सांसदों के बीच ताई के नाम से विख्यात श्रीमती सुमित्रा महाजन के नाम का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके बाद सर्वसम्मति से सदन ने उन्हें लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया।

श्रीमती महाजन ने कहा कि इस बार 300 से ज्यादा सदस्य लोकसभा में पहली बार आए हैं। उन्हें संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली के बारे में प्रशिक्षण देने की जरूरत है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि उनकी कोशिश सदन पटल पर सभी पार्टियों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने की कोशिश होगी, ताकि राष्ट्रहित के मुद्दों पर सकारात्मक बहस हो सके। इसके साथ ही सदन में छोटी-छोटी पार्टियों को अपनी बात रखने का मौका देने की कोशिश करेंगी।

इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमती सुमित्रा महाजन को बधाई देते समय उनका परिचय विशिष्ट अंदाज में कराया। उन्होंने श्रीमती महाजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके नाम में ही मित्रता है। संस्कृत के एक श्लोक का उल्लेख करते हुए कहा कि महाजन जिस राह पर चलते हैं, उस राह पर चलना चाहिए, जबकि यहां तो सदन में महाजन खुद विराजमान हैं। आशा है कि सदन सही राह पर चलेगा।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इंदौर नगर निगम में सामान्य सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने वाली महाजन लोकसभा के लिए आठ बार चुनी गई हैं। उन्हें संसद में काम करने का लंबा अनुभव है, जो सदन के सुचारू संचालन के लिए काफी उपकारक सिद्ध होने वाला है। श्रीमती मीरा कुमार के बाद श्रीमती सुमित्रा महाजन के रूप में देश को लगातार दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष मिली हैं।

उन्हें 6 जून को कार्यवाहक लोकसभा अध्यक्ष श्री कमलनाथ ने कार्यभार ग्रहण कराया। श्री मोदी के बाद सदन में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्नाद्रमुक के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता सहित कई दलों के सदस्यों ने महाजन को बधाई दी।

पृष्ठ 9 का शेष...

और अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ वहां लॉन में बैठे रहे। दिल्ली भाजपा के कुछ नेतागण उनके साथ थे जिनमें दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और सांसद डा. हर्षवर्धन, दिल्ली भाजपा संगठन प्रभारी श्री प्रभात झा, पूर्व भाजपा अध्यक्ष श्री विजय गोयल, और श्री विजेन्द्र गुप्ता, पूर्व दिल्ली महापौर श्रीमती आरती मेहरा और दिल्ली से नवनिर्वाचित सांसदगण शामिल हैं। इसके बाद श्री मोदी सीधे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीअटल बिहारी वाजपेयी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके निवास पर गए। दिल्ली से सभी लोकसभा सदस्य तथा अन्य भाजपा वरिष्ठ नेता उनके साथ थे।

श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने से देश और भाजपा के लिए एक नए युग की शुरूआत हो गई है। भाजपा ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर पूरे राष्ट्र को एकजुट करने का दशकों से संघर्ष किया है और भाजपा ने छद्म सेक्युलिरस्टों की नीतियों के खिलाफ अभियान चलाए हैं। जिस भावना से भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में श्री मोदी के शपथ ग्रहण का जश्न मनाया है, उससे स्पष्ट है कि पार्टी लोगों की महत्वाकांक्षाओं और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु निर्माण का काम करेगी। ■

रचनात्मक विपक्ष का अभाव

✍ हृदयनारायण दीक्षित

इतिहास की धारा मोड़ना आसान नहीं होता। इस धारा में आनंदवर्धन अध्याय जोड़ना और भी कठिन होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने चमत्कार किया है। चुनाव अभियान में, जनसंवाद में और राष्ट्रवाद को सभी भौगोलिक व सामाजिक क्षेत्रों तक जनस्वीकृति दिलाने में भी। उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। जनादेश ने कांग्रेस को इतिहास और पुरातत्व की सामग्री बना दिया है। सत्तापक्ष में 336 सांसद हैं। संसदीय जनतंत्र वाद-विवाद संवाद से चलता है। कांग्रेस सहित विपक्ष की किसी भी पार्टी के पास मान्यता प्राप्त विरोधी दल बनने के लिए सदन की न्यूनतम संख्या भी नहीं है। विपक्ष में अनुभव और तर्कशक्ति संपन्न वरिष्ठ नेताओं का भी अभाव है। सत्तापक्ष में मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जैसे अनुभवी, प्रतिभाशाली दिग्गज प्रथम पंक्ति में बैठेंगे तो विरोधी कतारों में सोनिया गांधी, मुलायम सिंह और राहुल। वामदल नगण्य हैं। तृणमूल और अन्नाद्रमुक के सांसदों से भी प्रभावी और रचनात्मक विरोध की उम्मीद नहीं है। संसदीय व्यवस्था में बहुमत के पास सरकार चलाने का जनादेश होता है तो अल्पमत के पास रचनात्मक विरोध का। लेकिन विपक्ष कमजोर है, कुंठाग्रस्त भी है।

कांग्रेस कुछ ज्यादा ही कुंठाग्रस्त है और बाकी दल हीनभाव में हैं। मोदी सरकार जिम्मेदारी के साथ चल पड़ी है। कांग्रेस को भी खुलेमन से जनादेश का स्वागत करना चाहिए और शालीन विपक्ष की भूमिका में जुट जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने एक मंत्री स्मृति ईरानी की नियुक्ति पर स्तरहीन टिप्पणी की। संसदीय परंपरा में कम से कम छह माह तक नई सरकार का कामकाज देखा जाता है। अटलजी बहुधा ऐसा ही कहते और करते थे। आखिरकार विपक्ष गैर-जिम्मेदार क्यों है? भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष की भूमिका सबसे पहले कांग्रेस के एक धड़े कांग्रेस को ही मिली। कांग्रेसी नेता डॉ. रामसुभग सिंह विपक्ष के नेता रहे। विपक्ष की भूमिका नगण्य थी, समाजवादी जनसंघी संख्या बल में कम होकर भी प्रभावी थे। हेराल्ड लास्की ने विपक्ष के तीन काम बताए थे। पहला सरकार को सुझाव देना, दूसरा विरोध करना और तीसरा सरकार को हटाने का संवैधानिक प्रयास करना। कांग्रेस ने मोदी सरकार को कोई सुझाव नहीं दिए। वह सुझाव देने की स्थिति में है भी नहीं। वह स्वयं दस बरस से सत्ता में थी। संसदीय परिपाटी में विपक्ष प्रतीक्षारत सरकार कहा जाता है। कांग्रेस में प्रतीक्षा का गुण नहीं है।

प्रधानमंत्री ने सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा, सबसे वार्ता की। पाकिस्तान से भी वार्ता हुई, लेकिन नवाज शरीफ के निमंत्रण के औचित्य पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने सख्त टिप्पणी की। कांग्रेस विपक्ष की मर्यादा में विश्वास नहीं करती। वह विरोध के लिए ही विरोध करती है। कारगिल घुसपैठ पर संसद में बहस हुई। कांग्रेस ने आपत्तिजनक बातें कीं। राष्ट्रीय आपदा या युद्ध जैसी स्थिति में विपक्ष सरकार से सहयोग करता है। अटलजी ने युद्ध के समय इंदिरा गांधी की प्रशंसा की थी, लेकिन कांग्रेस ने विपक्षी की हैसियत से कारगिल घुसपैठ और परमाणु परीक्षण पर हुई बहस में वही सब कहा, जो पड़ोसी देश कह रहा था। भारतीय जन-गण-मन ने मोदी पर विश्वास किया है। कांग्रेस सहित तमाम दलों को विपक्ष में बैठकर सारवान टिप्पणियां करने का ही काम सौंपा है। एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेराल्ड मैकमिलन ने दिलचस्प

इतिहास की धारा मोड़ना आसान नहीं होता। इस धारा में आनंदवर्धन अध्याय जोड़ना और भी कठिन होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने चमत्कार किया है। चुनाव अभियान में, जनसंवाद में और राष्ट्रवाद को सभी भौगोलिक व सामाजिक क्षेत्रों तक जनस्वीकृति दिलाने में भी। उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया। जनादेश ने कांग्रेस को इतिहास और पुरातत्व की सामग्री बना दिया है। सत्तापक्ष में 336 सांसद हैं। संसदीय जनतंत्र वाद-विवाद संवाद से चलता है। कांग्रेस सहित विपक्ष की किसी भी पार्टी के पास मान्यता प्राप्त विरोधी दल बनने के लिए सदन की न्यूनतम संख्या भी नहीं है।

बात कही थी, विपक्ष के नेता की स्थिति से अफलदायक स्थिति और किसी की नहीं होती। उसे आलोचना करनी पड़ती है। दोष निकालना उसका काम है। उसे अपनी स्थापनाएं और नीतियां स्पष्ट करनी पड़ती हैं। जबकि उन्हें कार्यरूप देने की शक्ति उसके पास नहीं होती। संसदीय व्यवस्था का सौंदर्य है विपक्ष। डॉ. लोहिया, अटल जी, कामरेड भूपेश गुप्त, पीलू मोदी, आडवाणी और सुषमा ने विपक्ष की भूमिका में रहकर संसदीय प्रणाली को नए तेवर और प्रतिमान दिए हैं। संविधान सभा में भी विपक्ष संख्या बल में कमजोर था, लेकिन विद्वान विपक्षी सदस्यों ने सभा के वाद-विवाद को प्राणवान, गतिशील और रचनात्मक बनाया। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हरिविष्णु कामथ, मौलाना हसरत मोहानी, विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी और नजीरूद्दीन अहमद आदि वरिष्ठों ने कार्यवाही को गतिशील बनाया। डॉ. अंबेडकर ने संविधान निर्माण के अंत में कहा कि विपक्ष न होता तो कार्यवाही उबाऊ और थकाऊ हो जाती, मुझे बहुमूल्य सुझाव मिले हैं।

मोदी सरकार भारत को विश्व प्रतिष्ठ बनाने की राह पर चल पड़ी है। गैर राजग दलों को भी राष्ट्र सर्वोपरिता के लक्ष्य का समर्थन करना चाहिए। जनादेश जाति, पंथ, मजहब और क्षेत्रवाद के विरुद्ध आया है। चीन, अमेरिका सहित सभी देश भौचक हैं। राष्ट्र निर्माण, विकास और सुशासन पर कोई मतभेद नहीं हो सकते। बेशक प्रक्रिया और नीतिगत मुद्दों पर विचार भिन्नता हो सकती है, लेकिन भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के 'मोदी स्वप्न' पर मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष की सबसे बड़ी संख्या वाली, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी राष्ट्रीय विकास, सुशासन और समृद्ध भारत के स्वप्न से स्वयं को प्रतिबद्ध कर सकती है? क्या उसके चित्ता में रचनात्मक और स्वस्थ विरोधी दल होने की क्षमता है? क्या वह करारी पराजय की कुंठा से उबर सकती है? प्रश्न ढेर सारे हैं- क्या अन्य दल विरोध के लिए ही विरोध करने की लत से मुक्ति पा सकते हैं? क्या नेशनल कांफ्रेंस जैसे दल जम्मू-कश्मीर को निजी संपत्ति की तरह ही देखने और राष्ट्रभाव को चुनौती देने का दुस्साहस छोड़ सकते हैं? ऐसी संभावनाएं हैं भी और नहीं भी।

मोदी सरकार भारत को विश्व प्रतिष्ठ बनाने की राह पर चल पड़ी है। गैर राजग दलों को भी राष्ट्र सर्वोपरिता के लक्ष्य का समर्थन करना चाहिए। जनादेश जाति, पंथ, मजहब और क्षेत्रवाद के विरुद्ध आया है। चीन, अमेरिका सहित सभी देश भौचक हैं। राष्ट्र निर्माण, विकास और सुशासन पर कोई मतभेद नहीं हो सकते। बेशक प्रक्रिया और नीतिगत मुद्दों पर विचार भिन्नता हो सकती है, लेकिन भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने के 'मोदी स्वप्न' पर मतभेद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मूलभूत प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष की सबसे बड़ी संख्या वाली, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस भी राष्ट्रीय विकास, सुशासन और समृद्ध भारत के स्वप्न से स्वयं को प्रतिबद्ध कर सकती है? क्या उसके चित्ता में रचनात्मक और स्वस्थ विरोधी दल होने की क्षमता है?

इतिहास में तमाम असंभव घटित हुए हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में विजय ऐसी ही घटना है। 2014 का ऐसा जनादेश न टिप्पणीकार सोचते थे और न ही चुनाव विश्लेषक, लेकिन मोदी के करिश्माई नेतृत्व में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण समान विचार प्रवाह की आंधी आई। राजग को सत्ता मिली। कांग्रेस आदि को रचनात्मक विरोध का जनादेश मिला। पं. जवाहर लाल नेहरू ने सत्तापक्ष और विपक्ष के सहयोग पर बल दिया था कि संसदीय प्रणाली में न केवल सशक्त विरोधी पक्ष की आवश्यकता होती है, बल्कि सरकार और विरोधी पक्ष के बीच सहयोग का आधार भी आवश्यक होता है। लेकिन कांग्रेस पं. नेहरू से भी प्रेरित नहीं होती। राबर्ट ए. दाहल ने अपनी खूबसूरत किताब 'पॉलिटिकल अपोजीशन इन डेमोक्रेसीज न्यू हैवेन' में प्रतिपक्ष की तीन किस्में गिनाई हैं। पहली परिवर्तन की इच्छा से युक्त सिद्धांतनिष्ठ प्रतिपक्ष। दूसरा सुधारवादी मगर नीतिविहीन प्रतिपक्ष और तीसरा दबाव की राजनीति करने वाला असंगठित प्रतिपक्ष।

वामदल और भाजपा अपनी पारी में पहले किस्म के प्रतिपक्ष रहे हैं और कांग्रेस तथा अन्य तीसरी श्रेणी वाले। जनादेश ने कांग्रेस को इसीलिए मुख्य विपक्षी दल की भूमिका भी नहीं दी। समय का आह्वान न सुनने वाले कालरथ के पहिये में दब जाते हैं। इतिहास क्षमा नहीं करता। ■

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के सदस्य हैं)

(साभार- दै. जागरण)

किसानों और वंचितों की आवाज थे मुंडे

तरुण विजय

विजय यात्रा की तैयारी के उत्सव का अचानक शोक यात्रा के हृदयद्रावक दृश्य में बदलना जीवन का एक ऐसा कठोर सत्य है, जो गोपीनाथ मुंडे के निधन से पुन: प्रकट हुआ है। वह दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, जहां अपने निर्वाचन क्षेत्र में विजय यात्रा में उन्हें शामिल होना था। लेकिन 16वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही दुखद दुर्घटना में नियति ने उन्हें छीन लिया।

महाराष्ट्र में जमीन से जुड़े, अपार जनसमर्थन के धनी, गरीब किसान, दलित पिछड़ों की राष्ट्रीय फलक पर आवाज बने गोपीनाथ मुंडे का जीवन संघर्ष और साहस का मिश्रण रहा। किसी से दबे नहीं, नुकसान सहकर भी समझौते न करने की जिद्द दिखाई। उनका व्यक्तित्व ही था कि राजनीति में 'न्यायाधीश' बन सजा और बख्शीशें देने वालों की उन्होंने बित्ते भर भी परवाह नहीं की। उन्होंने बताया कि अगर जमीन पर कदम है, जनता में स्नेह और समर्थन है, अपनी ताकत पर विश्वास है, तो भविष्य भी मुट्ठी में ही रहेगा।

वह बंजारा समुदाय से थे, पिछड़े वर्ग के, लेकिन जनजातीय समाज, अनुसूचित जातियों और किसानों में समान रूप से लोकप्रिय थे। संसद में 100-100 से अधिक किसान प्रतिनिधिमंडलों को बुलाते, उनसे मिलते, और उन्हें संसद भवन दिखाते। इतनी ही सहजता से वह जापान, चीन के प्रतिनिधिमंडलों से भी संसद के भाजपा कार्यालय में बात करते थे। पेड़ के नीचे जिस गोपीनाथ ने कभी शिक्षा पाई, वह भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री पद तक पहुंचे, तो इसके पीछे उनकी अपनी मेहनत और लगन का हाथ था। वह नई सोच के धनी थे। इसलिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार संभालने के बाद ही वह मनरेगा जैसी योजना में भी बदलाव की बात कह रहे थे, ताकि गरीबों को साल में सौ दिन का रोजगार हकीकत बन सके।

उनकी जोड़ी- प्रमोद महाजन के साथ अप्रतिम और बेहद प्रभावशाली

महाराष्ट्र में जमीन से जुड़े, अपार जनसमर्थन के धनी, गरीब किसान, दलित पिछड़ों की राष्ट्रीय फलक पर आवाज बने गोपीनाथ मुंडे का जीवन संघर्ष और साहस का मिश्रण रहा। किसी से दबे नहीं, नुकसान सहकर भी समझौते न करने की जिद्द दिखाई।

थी। बाला साहब ठाकरे के साथ महाजन-मुंडे बेहद करीबी और अंतरंग संबंध रखते थे। विधि की कैसी विडंबना है कि उनके अन्यतम साथी, मित्र और साले प्रमोद महाजन भी अकाल मृत्यु का शिकार हुए। महाजन के परिवार को संभालना, सुख-दुख की चिंता, राहुल और पूनम का हाथ थामना- यह सब गोपीनाथ मुंडे ने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी समझकर किया था। अपनी आत्मीयता से हजारों कार्यकर्ताओं को साथ में लिए चलना और ऐसा साथ निभाना कि हर आरोह-अवरोह में वह साथ खड़ा दिखें। ऐसे गुण थे कि तमाम आघातों के बावजूद कोई उन्हें महाराष्ट्र की धुरी से खारिज नहीं कर पाया।

महाराष्ट्र, जहां मराठा राजनीति का वर्चस्व यशवंत राव चव्हाण सरीखे नेताओं के समय से ही स्थापित था और जिनके रक्षा मंत्री बनने पर सह्याद्रि के पास हिमालय आया जैसे मुहावरे गढ़े गए, गोपीनाथ मुंडे के जमीनी राजकाज और हिम्मत, कई बार अतिक्रमण करते हुए साहसी राजनीति के कारण भाजपा के पक्ष में आया और मुंडे उस महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री बने, जहां भाजपा को हाशिये की पार्टी बताया जाता था। आसन्न विधानसभा चुनावों में उनकी प्रमुख भूमिका रहने वाली थी। वह मुख्यमंत्री हो सकते थे।

दिल्ली की राजनीति और आम माहौल में पैसे के अहंकार, पद से जन्मी तुनकमिजाजी और असभ्यता हवा में घुली रहती है। यहां अंधी रफ्तार सड़क पर बिखरी रहती है और गाड़ियां नियम, लाल बत्ती या राह पर चलने के दूसरे के अधिकार को अस्वीकार करती हैं। गोपीनाथ मुंडे भारत के स्वप्निल ग्रामीण विकास मंत्री और गरीब पिछड़े वर्ग की धमकदार राष्ट्रीय आवाज इसी असभ्य दिल्लीपन का शिकार हो गए। विजयोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे एक धरती पुत्र को भारत ने गंवा दिया।■

(लेखक भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं)

(साभार- अमर उजाला)

कालाधन पर पहली बार ऐसे तेवर

✍ जोगिन्दर सिंह

मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला किया, वह है- कालेधन की जांच और निगरानी के लिए विशेष जांच दल का गठन।

जिस तरह त्वरित तौर पर यह फैसला लिया गया, उसके लिए सरकार को धन्यवाद मिलना ही चाहिए। प्रत्यक्ष तौर पर साफ दिख रहा है कि सरकार की मंशा साफ है। हालांकि यह संभव है कि आगे वे लोग अलग तरह का दवाब बनाने की कोशिश करें जिनका धन वहां जमा है। हो सकता है, इसमें वैसे लोग भी हों जो सत्ताधारी दल के करीबी हों। लेकिन प्रधानमंत्री की मंशा और रवैया देखते हुए साफ है कि ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे।

भाजपा लंबे समय से काले धन की वापसी का मसला उठाती रही है। 2009 के चुनाव के दौरान लालकृष्ण आडवाणी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था और इस बार के चुनाव में विभिन्न मंचों से नरेंद्र मोदी ने बार-बार इस मुद्दे को लेकर यूपीए सरकार को घेरा। इतना ही नहीं, भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जनता से वादा किया कि सरकार बनने के 150 दिन के अंदर विदेशों में जमा काले धन को वापस ला दिया जाएगा। योगगुरु बाबा रामदेव जो भाजपा के करीबी रहे हैं, ने भी इस काले धन की वापसी को लेकर आक्रामक तेवर दिखाए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि सरकार इस मसले पर अपना ध्यान केंद्रित करती, लेकिन यह सब इतनी जल्दी होगा, यह किसी ने नहीं सोचा था।

जिस तरह त्वरित तौर पर यह फैसला लिया गया, उसके लिए सरकार को धन्यवाद मिलना ही चाहिए। प्रत्यक्ष तौर पर साफ दिख रहा है कि सरकार की मंशा साफ है। हालांकि यह संभव है कि आगे वे लोग अलग तरह का दवाब बनाने की कोशिश करें जिनका धन वहां जमा है। हो सकता है, इसमें वैसे लोग भी हों जो सत्ताधारी दल के करीबी हों। लेकिन प्रधानमंत्री की मंशा और रवैया देखते हुए साफ है कि ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे।

बहरहाल, यह फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। गौर करने वाली बात है कि काले धन के कारोबार पर नकेल कसने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ही विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का फैसला लिया था। न्यायालय की ओर से फैसला लेने का कारण यह था कि उस समय दिल्ली पर काबिज मनमोहन सरकार इस मसले पर आनाकानी कर रही थी। कालेधन का मुद्दा उस समय भी इतना गहराया हुआ था कि सरकार से अपेक्षा की गई थी कि वह आनन-फानन में एसआईटी का गठन करे।

परंतु सरकार ने ऐसा नहीं किया और किंतु-परंतु के खेल में सुप्रीम कोर्ट और जनता को गुमराह करने का काम किया। सरकार ने तो बाद में साफ-साफ यह कहना भी शुरू कर दिया कि एसआईटी का गठन देश के लिए अच्छा कदम नहीं होगा। सरकार ने आखिर पुनर्विचार याचिका भी दायर की। ऐसा आम जनता की सोच को अनदेखा कर किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ गंभीरता से वाच कर रही थी और उसकी सक्रियता का ही नतीजा रहा कि कोर्ट ने कुछ समय पहले एक बार फिर एसआईटी के गठन की बात कही। इस बार तो उसने इसका खाका भी तैयार कर सामने रखा। इतना होते हुए भी यूपीए सरकार फैसले को मानने से बचती रही और आखिर में उसने हाथ तक खड़े कर दिए।

मोदी सरकार इस मामले में एक्शन में आ तो गई है लेकिन आगे जरूरत इस बात की है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास जारी रखे। नहीं भूला जाना चाहिए कि विदेशों में मौजूद काले धन की अगर देश वापसी होती है तो आर्थिक मोर्चे पर परेशानी झेल रहे देश को काफी हद तक राहत मिलेगी। अमेरिकी संस्था जीएफआई के 2008 के अनुमान के मुताबिक भारत का करीब 23 लाख करोड़ का काला धन और भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ फिक्की के आंकड़ों के मुताबिक करीब 45 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में जमा है। दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक स्विस बैंकों में भारतीयों के करीब 85 अरब करोड़ रुपए जमा थे। सवा अरब आबादी वाले इस देश का सालाना बजट भी इससे कम है।

एसआईटी के गठन के बाद काले धन को लाने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। पिछली सरकार ने जर्मनी की

सरकार के कहने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया था। यह साफ है कि कई विदेशी सरकारें इस मुद्दे पर जानकारी साझा करने को तैयार हैं। वे दूसरी तरह की मदद भी करने को राजी हैं लेकिन हमने ही अब तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बल्कि किसी न किसी तरह इस मुद्दे को टालने में लगे थे। पहले यह संभव था कि सरकार कोई एमनेस्टी स्कीम लाती और टैक्स छूट के नाम पर लोगों को काले धन को सफेद बनाने का मौका दिया जाता। सरकार के पास यह विकल्प पहले बिल्कुल खुला था लेकिन जैसे-जैसे मसला कोर्ट में जड़े जमाता रहा सरकार के हाथ से यह विकल्प निकल गया।

सुप्रीम कोर्ट में इसी अप्रैल में तत्कालीन सरकार ने उन 18 लोगों की जानकारी दी थी जिन्होंने कथित रूप से जर्मनी के लिचेंस्टीन में स्थित एलएसटी बैंक में काला धन जमा कर रखा था और जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने जांच भी शुरू कर दी है। इतना होते हुए भी इन लोगों के नाम जाहिर नहीं किए गए थे। आगे एक-एक कर नाम जाहिर किए जाने चाहिए। एसआईटी के नए अध्यक्ष (सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम वी शाह) और उपाध्यक्ष (सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरजीत पसायत) ने जल्द ही पहली बैठक कर मामले को तेजी से सुलझाने की बात कही है। एसआईटी को इस बात पर भी गंभीरता से विचार करना होगा कि कहीं यह काला धन दूसरे रास्ते से यहीं तो नहीं खप रहा। काला धन महज एक धारणा नहीं है बल्कि यह तथ्यात्मक रूप से भी हमारे सामने है। अब तक इन पर ज्यादा गौर नहीं किया गया है।

हमारे यहां एक धारणा बना दी गई है कि काले धन पर अंकुश लगाना

भाजपा लंबे समय से काले धन की वापसी का मसला उठाती रही है। 2009 के चुनाव के दौरान लालकृष्ण आडवाणी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था और इस बार के चुनाव में विभिन्न मंचों से नरेंद्र मोदी ने बार-बार इस मुद्दे को लेकर यूपीए सरकार को घेरा। इतना ही नहीं, भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जनता से वादा किया कि सरकार बनने के 150 दिन के अंदर विदेशों में जमा काले धन को वापस ला दिया जाएगा।

अदालत का काम है लेकिन इसके उलट सच्चाई यह है कि यूपीए सरकार के ढीले रवैये के कारण न्यायपालिका ने कार्यपालिका का काम अपने हाथों में लिया। काले धन के पीछे की मुख्य वजह भ्रष्टाचार ही है। स्विस बैंक में जो भी पैसा जमा है, भ्रष्टाचारियों की वजह से है। ये भ्रष्टाचारी कहां से आते हैं और इन्हें कौन शह देता है, इसकी जानकारी शायद सभी को है। राजनीति इसकी जड़ है। जनता को सोचना चाहिए कि काले धन को लेकर जागरूकता का परिचय देते हुए फैसला ले और वोट देने का आधार यह भी बनाए कि इस मोर्चे पर कौन कैसा काम कर रहा है!

दरअसल विदेशी बैंकों में जमा काला धन वह पैसा है जो अप्रत्यक्षत: लोगों की जेब से निकला है। भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को मिटाना है तो जनता का जागरूक होना ही प्राइमरी विकल्प है। चूंकि राजनीति जनता के दबाव में चलती है इसलिए लोगों को सचेत होना होगा। हालांकि भ्रष्टाचार और काला धन अब नौकरशाही और प्रशासन में भी घर कर गया है। इकोनॉमिक वर्ल्ड में तो इसकी पहुंच है ही। मैं खतरा यह देख रहा हूं कि जनता भी इसे जीवन का अनिवार्य अंग मानने लगी है।

वह इसे मुद्दा नहीं मानती लेकिन लोगों को समझाना होगा कि बगैर इसके मिटे देश का विकास संभव नहीं। इसका वजूद खत्म किए बिना न गरीबी मिट सकती है और न शिक्षा व स्वास्थ्य को सभी के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। भ्रष्टाचार मिटे और लोग काला धन संचय न कर पायें, इसके लिए न्यायपालिका को लगातार सक्रिय रहना होगा। काला धन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। काले धन से संबंधित जांच-पड़ताल में गुणवत्ता और मुकदमे की समय सीमा कम करना अत्यंत जरूरी है। इंकम टैक्स विभाग को भी अपनी कार्य प्रणाली में आमूल सुधार करना होगा।

हालांकि फिलहाल काले धन को वापस लाना इतना आसान नहीं होगा लेकिन आगे इतना जरूर होगा कि इसका प्रवाह विदेशी बैंकों की ओर रुकेगा। वैसे एसआईटी की जांच किस तरह की होगी, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। अगर यह पता चल जाए कि किनका पैसा विदेशी बैंकों में जमा है तो फिर वहां से ट्रांसफर किए जाने के बावजूद काले धन की वापसी हो सकती है। आखिर दोषियों पर सतत कार्रवाई और कालाधन जमा करने वालो को कड़ा संदेश दिया जाना जरूरी है। सीबीआई जैसी जांच इकाइयों को भी स्वतंत्र करने की जरूरत है ताकि बगैर किसी हस्तक्षेप के देश में काले धन का कारोबार कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जा सके। ■

(लेखक सीबीआई के प्रमुख रहे हैं)

(साभार- रा. सहारा)

दलित राजनीति की नई दिशा

✍ डॉ. उदित राज

पहली लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय दलित राजनीति कोई खास नहीं थी। दलितों व आदिवासियों में वोट की कीमत का अहसास नाममात्र ही था। हालांकि उस समय बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जीवित थे, फिर भी इस समाज में जागृति का बड़ा अभाव था। डॉ. भीमराव अंबेडकर स्वयं भी चुनाव हारे। समय बीतने के साथ-साथ समाज में जागृति आती गई और दलित राजनीति का प्रादुर्भाव धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ।

महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अस्तित्व में आई, लेकिन उसकी भी सफलता आंशिक ही रही। 1960 के दशक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित-मुस्लिम गठजोड़ आंशिक रूप से ही सफल रहा। वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन से दलित राजनीति के एक नए युग की शुरुआत हुई। हालांकि यह अलग बात है कि यह गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक नया प्रयोग किया और सवर्णों को भी उम्मीदवार बनाया गया। इसके पीछे सोच यही थी कि उनके अपने समाज का वोट तो है ही साथ में यदि उन्हें दलित समाज का भी वोट मिल जाता है तो निश्चित जीत की स्थिति में पहुंचा जा सकता है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में दलित व सवर्ण समीकरण ने वर्ष 2007 में एक बड़ी सफलता की इबारत लिखी, लेकिन वह वर्तमान लोकसभा चुनावों में ढह गया। आज प्रश्न यह है कि क्या अकेले दलित वोटों से मुख्यधारा की राजनीति में आया जा सकता है और बिना राजनीतिक मुख्यधारा में आए क्या अपने पक्ष में नीतियां बनवाई जा सकती हैं?

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से राजनीतिक ध्रुवीकरण 16वें लोकसभा चुनाव में हुआ उससे न केवल क्षेत्रीय समीकरण प्रभावित हुए, बल्कि दलित राजनीति भी। मुझे भी यह अनुमान नहीं था कि दलित राजनीति को इतना तगड़ा झटका लगेगा। इतनी समझ जरूर आ गई थी कि मुख्यधारा की पार्टी से बिना जुड़े दलितों, आदिवासियों व वंचितों के लिए नीतियां बनाई नहीं जा सकती हैं। मात्र पहचान बनाना अब काफी नहीं है, बल्कि भागीदारी चाहिए। भागीदारी से देश का सर्वांगीण विकास होगा और इससे खुशहाली व राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी। शुरू में मेरे साथियों को झटका सा लगा, जब ऐसा प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अंततः उन्हें मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा और 24 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। यह विचार मंथन अक्टूबर, 2013 से ही चल रहा था और संतोष की बात यह है कि चुनाव परिणाम ने हमारी सोच पर मुहर लगा दी। दलितों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन दिया। इनके झुकाव को बहुत सरलता से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक आशा और विश्वास इसके पीछे है।

इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी ने 20 मई को संसद में यह सही कहा कि लोगों ने वोट आशा और विश्वास को दिया है।

परंपरागत दलित राजनीति अब थक गई है। केवल मान-सम्मान की बात कहने से भागीदारी व आत्मनिर्भरता नहीं मिलने वाली है। दलित राजनीति का मुख्य प्रतीक बनी मायावती दलितों को वह भी नहीं दे रही हैं, जिसके लिए वे विशेष रूप से बसपा से जुड़े। दलित बुद्धिजीवियों में भारी निराशा है कि आरक्षण की वजह से जो भागीदारी पहले मिल रही थी, उसमें भी कटौती होती चली जा रही है। नई आर्थिक नीति के कारण तमाम रोजगार-व्यवसाय के अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन दलितों-आदिवासियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस दोनों में उदासीनता आई। इनका वोट जब क्षेत्रीय दलों में जाने लगा तो ऐसी स्थिति में इनके लिए केंद्र सरकारों की कुछ करने की इच्छाशक्ति भी कमजोर हुई।

इस बार के लोकसभा चुनाव में

इस बार के लोकसभा चुनाव में दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला, इसलिए इसका फल भी उन्हें जरूर मिलना चाहिए। गत 2 मार्च की लखनऊ रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाला दशक पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों व वंचितों का होगा और इसका असर व्यापक तौर पर हुआ।

20 मई को जिस तरह से संसद में नरेंद्र मोदी ने दलितों व गरीबों के उत्थान की बात कही, उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि उनकी सरकार इन्हें भागीदारी देगी। ऐसा होना अब संभव प्रतीत हो रहा है, इसलिए दलित मुख्यधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जरूर आएंगे।

दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला, इसलिए इसका फल भी उन्हें जरूर मिलना चाहिए। गत 2 मार्च की लखनऊ रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाला दशक पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों व वंचितों का होगा और इसका असर व्यापक तौर पर हुआ।

बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 19.6 प्रतिशत वोट मिला, जबकि राज्य में दलितों की आबादी 22 प्रतिशत है। मायावती ने 17 मई को कहा कि उनका दलित वोट खिसका नहीं है जो कि झूठ है। वह उन्हीं को टिकट देती हैं, जिनकी जाति का अच्छा-खासा वोट होता है। बहुजन समाज पार्टी के ताकतवर उम्मीदवारों का वोट फिर कहां गया? सच्चाई यह है कि इस बार अच्छा-खासा दलित वोट भारतीय जनता पार्टी में गया है। मायावती मनोवैज्ञानिक युद्ध के माध्यम से दलितों को भ्रमित करके अपना जनाधार बनाए रखना चाहती हैं। 20 मई को जिस तरह से संसद में नरेंद्र मोदी ने दलितों व गरीबों के उत्थान की बात कही, उससे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि उनकी सरकार इन्हें भागीदारी देगी। ऐसा होना अब संभव प्रतीत हो रहा है, इसलिए दलित मुख्यधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जरूर आएंगे।

अब भारतीय जनता पार्टी की वह छाप नहीं रह गई है कि यह सवर्णों की पार्टी है। यदि हम अपने समाज को जोड़ते हैं तो इस पार्टी का दिल छोटा नहीं है और वह दलितों को पूरा सम्मान देगी। दूसरी सबसे अच्छी बात यह हुई है कि सवर्ण व दलित के बीच जो खाई बढ़ती जा रही थी, अब वह कम हुई है और मुझे विश्वास है कि आगे और भी अच्छा होगा। जिस पार्टी का अंतिम लक्ष्य यह हो कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने तो यह स्वाभाविक है कि वह हर वर्ग को मान-सम्मान व भागीदारी दे। राष्ट्रीयता और कला-संस्कृति का बचाव तभी हो सकता है, जब राजनीतिक सत्ता पर कब्जा हो। मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक सुनहरा अवसर है कि देश के दलितों को मुख्यधारा की राजनीति में भागीदारी देकर न केवल अपने राजनीतिक, बल्कि सामाजिक जनाधार को भी मजबूत करे, ताकि वह राष्ट्र निर्माण में और अधिक सशक्त भूमिका निभा सके। ■

(लेखक भाजपा के लोकसभा के सदस्य हैं)

(साभार- दै. जागरण)

बदायूं बलात्कार कांड :

भाजपा महिला मोर्चा ने घेरा मुख्यमंत्री कार्यालय

उत्तर प्रदेश में बदायूं बलात्कार और हत्या मामला सामने आने के बाद भाजपा सपा सरकार पर और ज्यादा हमलावर हो गई है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने 2 जून को लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा ने ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दफ्तर का घेराव किया है।

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय के बाहर रोक लिया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में संघर्ष भी हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की। इस पर भाजपा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई तो इसका तगड़ा जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ भाजपा ने एक बार फिर अखिलेश यादव के इस्तीफे की मांग दोहराई।

भाजपा महिला मोर्चा की ओर से किए गए प्रदर्शन का नेतृत्व मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह कर रही थीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मांग की कि बदायूं बलात्कार मामले में मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। ■

गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे

श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता

महाराष्ट्र की राजनीति की जमीन से उठे और केन्द्र में भाजपा सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के पद तक पहुंचे श्री गोपीनाथ मुंडे का 3 जून को नई दिल्ली में एक सड़क हादसे के बाद निधन हो गया। वह 65 वर्ष के थे और अपने पीछे तीन बेटियां छोड़ गए हैं जिनमें से 2 ब्याहता हैं। छोटी बेटी लॉ की पढ़ाई कर रही है। बड़ी बेटी महाराष्ट्र की पर्ली सीट से विधायक हैं। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा कार्यालय जाकर उनके पार्थिव शव पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए वहां उपस्थित उनकी बेटियों को सांत्वना दी। वह पार्टी में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक प्रभावी नेता थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी, अनेक केंद्रीय मंत्रियों समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने 3 जून को भाजपा मुख्यालय पर स्व. गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री मुंडे का 3 जून की सुबह सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था।

स्व. मुंडे का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए अशोक रोड स्थित भाजपा मुख्यालय लाया गया। राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से मुंडे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी भी स्व. मुंडे को श्रद्धांजलि देने भाजपा मुख्यालय आए। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने केंद्रीय मंत्री स्व. गोपीनाथ मुंडे के परिवार को एक व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।

दोपहर करीब एक बजे स्व. मुंडे के पार्थिव शरीर को सेना के वाहन से भाजपा मुख्यालय लाया गया, जिस पर उनकी पुत्रियां एवं परिवार के सदस्यों के अलावा केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और डॉ. हर्षवर्धन सवार थे। गमगीन एवं भावुक माहौल में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्व. मुंडे को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर उनकी पुत्रियों को ढांढस बंधाया। पार्टी मुख्यालय पर भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू, रेल मंत्री श्री सदानंद गौड़ा, कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री श्री नितिन गडकरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी, मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, पार्टी राष्ट्रीय महासचिव श्री अमित शाह आदि

ने भी महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता श्री मुंडे को श्रद्धांजलि दी।

सभी नेता श्री मुंडे के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे थे और वहां मौजूद उनकी बेटियों को ढांढस बंधा रहे थे। भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं लोजपा के श्री राम विलास पासवान, शिवसेना के श्री अनंत गीते और नेशनल पीपुल्स पार्टी के प्रमुख श्री पीए संगमा और उनकी बेटी सुश्री अगाथा संगमा सहित अनेक नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जदयू अध्यक्ष श्री शरद यादव और बीजद के श्री जय पांडा भी भाजपा मुख्यालय पहुंचे। राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी भाजपा मुख्यालय में श्री मुंडे को श्रद्धांजलि दी।

भाजपा मुख्यालय पर काफी गमगीन माहौल था, जहां न सिर्फ भाजपा नेता बल्कि कार्यकर्ता भी भारी संख्या में मुंडे के अंतिम दर्शन के लिए पार्टी मुख्यालय उमड़ पड़े। ■

वरिष्ठ नेताओं ने जताया शोक

अपने मित्र और सहयोगी गोपीनाथ मुण्डेजी के निधन से मुझे अत्यंत दु:ख और आघात पहुंचा है। उनका निधन पूरे देश और सरकार के लिए बहुत बड़ी हानि है। गोपीनाथ मुण्डेजी वास्तव में जननेता थे। समाज के पिछड़े वर्ग में जन्म लेकर भी वे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे और अथक परिश्रम से उन्होंने लोगों की सेवा की। इस महान नेता को मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि है, जिनकी असामयिक मृत्यु के कारण एक शून्यता पैदा हो गई, जिसे भरा नहीं जा सकता है। मुण्डेजी के परिवार को मेरा हार्दिक सहानुभूति है। इस दु:ख की घड़ी में हम सभी उनके साथ हैं।

– नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत सरकार

भाजपा नेता श्री गोपीनाथ मुंडे का निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है।

– राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा एवं केन्द्रीय गृहमंत्री

मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी के निधन के समाचार से स्तब्ध हूं।

–सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री

मैं स्तब्ध हूं। मैंने एक मित्र खो दिया है।

– अरुण जेटली, वित्त मंत्री

मुंडे के पास दलितों, किसानों और पिछड़ों के उत्थान के लिए बड़े सपने थे। वे उनके लिए काफी कुछ करना चाहते थे।

– एम वेंकैया नायडू, शहरी विकास मंत्री

देश ने एक महान नेता खो दिया है। वह ऐसे नेता थे, जिनके पास संगठन और प्रशासनिक मुद्दों दोनों को लेकर दृष्टि थी।

– नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री

वह न सिर्फ एक नेता थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। उनका अचानक चले जाना बड़ा आघात है।

– रवि शंकर प्रसाद, कानून मंत्री

मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह अब हमारे बीच नहीं रहे। वह सही मायनों में महाराष्ट्र के जन नेता थे। मेरा उनसे 42 वर्षों से संबंध रहा है। उनका निधन महाराष्ट्र, देश और मेरे लिए बड़ा आघात है।

–प्रकाश जावड़ेकर, सूचना प्रसारण मंत्री

यह काफी दुखद है कि मुंडेजी हमारे बीच नहीं हैं। काल कितना निष्ठुर हो सकता है, यह स्पष्ट होता है। कल तक वे हमारे बीच थे, कैबिनेट की बैठक में हमने चर्चा की और आज उनका निधन हो गया। यह अपूरणीय क्षति है।

–रामबिलास पासवान, उपभोक्ता, खाद्य एवं जन वितरण मंत्री

यह स्तब्ध करने वाली खबर है। हमने एक गतिशील जन नेता खो दिया।

– शरद पवार, राकांपा नेता

मुंडे का असामयिक निधन दुखद और स्तब्ध करने वाला है।

– पी चिदंबरम, पूर्व वित्त मंत्री

मुंडे जी के निधन से भारत की जनता विशेषकर महाराष्ट्र की जनता ने एक महान सांसद, व्यक्ति और सच्चा देशभक्त खो दिया।

– जे जयललिता, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री

असामयिक निधन की खबर सुनकर गहरा सदमा पहुंचा है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और दुख की इस घड़ी में परिवार को इस शोक को सहने की ताकत दे।

– उमर अब्दुल्ला, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री

मुंडे जी का निधन देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उनमें गजब की क्षमता थी। विकास का सूरज डूब गया।

– शिवराज सिंह चौहान, म.प्र. के मुख्यमंत्री

शिवसेना और भाजपा ने ही एक शानदार नेता नहीं खोया है बल्कि महाराष्ट्र को भी अपूरणीय क्षति हुई है।

– संजय राउत, शिवसेना के प्रवक्ता

आंतरिक सुरक्षा के लिए एकीकृत योजना बनाई जाएगी : राजनाथ सिंह

देश की पंगु हो चुकी व्यवस्था में प्रभावी बदलाव के लिए समय चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा के लिए एकीकृत योजना बनाए जाने की बात कही। केंद्रीय गृहमंत्री का पदभार संभालने के बाद 7 जून को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे श्री राजनाथ सिंह ने नवगठित मोदी सरकार द्वारा जनता से किए गए वादे पूरा करने का संकल्प दोहराया।

पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में श्री सिंह के निशाने पर पूर्ववर्ती संप्रग सरकार रही। उन्होंने बताया, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने नक्सलवाद, आतंकवाद एवं अलगाववाद के संकटों का समाधान करने को व्यापक एकीकृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यह काम वर्षों पहले हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका। इस कार्ययोजना के आधार पर संतुलित कार्रवाई होगी। देश का गौरव व सम्मान बचाने के लिए सरकार प्रत्येक आवश्यक कदम उठाएगी। श्री सिंह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करना भी नहीं भूले। कहा, प्रधानमंत्री गतिशील व्यक्तित्व व कल्पना क्षमता के धनी हैं। पांच साल में वह जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे।

मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह में दक्षेस के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि बनने का श्रेय श्री मोदी को देते हुए कहा कि भारत पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध चाहता है। केवल दक्षिण एशिया ही नहीं विश्व में भारत की साख बनाने की जरूरत है। इससे पूर्व लखनऊ पहुंचे श्री राजनाथ सिंह को भाजपा कार्यकर्ता बड़े जुलूस के साथ अमौसी हवाई अड्डे से पार्टी मुख्यालय तक लाए। केसरिया झंडों व बैनरों से सजाए रास्ते में भी जगह-जगह स्वागत किया गया। ■

भाजपा कार्यालय की जमीन से ऊर्जा मिलती है : नरेन्द्र मोदी

भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले श्री नरेंद्र मोदी ने जीत का सेहरा कार्यकर्ताओं के सिर बांधा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार भाजपा मुख्यालय पहुंचे श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने कहा, 'पांच अक्षरों वाले शब्द प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ा चार अक्षरों वाला कार्यकर्ता होता है।' नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं पार्टी मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच संक्षिप्त भाषण में उन्होंने असीमित संदेश दे दिया। लक्ष्य था कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना। भाजपा में उन्होंने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और कहा कि उन्हें भाजपा कार्यालय की जमीन से ऊर्जा मिलती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो वह खुद उनसे आग्रह करने गए थे कि अशोका रोड आइए। यहां कई नेताओं ने तपस्या की है। कार्यकर्ताओं के साथ इस जुड़ाव को मजबूत करने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि विधानसभा चुनावों में भी मोदी ही पार्टी का संभवतः एकमात्र चेहरा होंगे। ■

ताराकांत झा का निधन

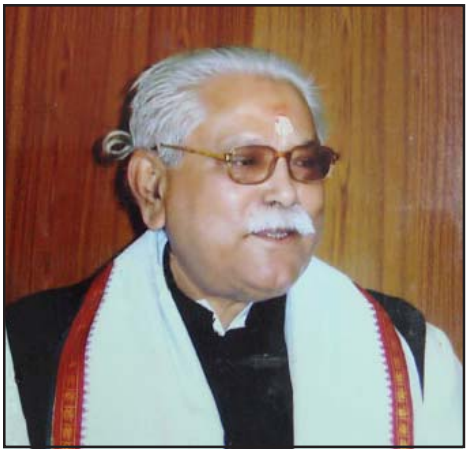

बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति श्री ताराकांत झा का 11 मई 2014 को पटना स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अनुमंडल के शिवनगर गांव में जन्मे 86 वर्षीय दिवंगत ताराकांत झा काफी दिनों से अस्वस्थ थे। उनके परिवार में पत्नी, एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। वर्ष 1952 से आरएसएस एवं जनसंघ से जुडे रहे तथा भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे श्री झा ने संगठन को मजबूत करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का दायित्व संभाल चुके श्री झा पेशे से वकील और बिहार के महाधिवक्ता के पद पर भी आसीन रहे। इसके साथ ही वे बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष तथा छह वर्षों तक बार काउंसिल आफ इंडिया के सदस्य रहे थे तथा मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह द्वारा श्री ताराकांत झा के निधन पर शोक संदेश

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने बिहार के विधायी परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्री ताराकांत झा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।

श्री झा प्रख्यात न्यायविद्, जनसाधारण राजनीतिज्ञ थे। वह 86 वर्ष के थे और संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल कराने का सदैव प्रयास किया।

यद्यपि वह आज हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु उनके कार्य तथा जिन सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, वे हमारे लिए सदैव मार्गदर्शक बने रहेंगे। ■

नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री तपन सिकदर

पश्चिम बंगाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री तपन सिकदर का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में निधन हो गया। 2 जून की सुबह 6.30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। वे 70 साल के थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह और वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी समेत अनेक नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अविवाहित रहे श्री तपन सिकदर दमदम लोकसभा क्षेत्र से दो बार सांसद चुने गए। वे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राज्यमंत्री रह चुके थे।

वरिष्ठ भाजपा नेता को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है-''तपन सिकदरजी का जाना बेहद दुखद है। उनकी आत्मा को शांति मिले। वे भाजपा के निर्माण में अपने बहुमूल्य योगदान और सालों तक जनसेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए याद किए जाएंगे।'' ■

वामपंथी शासन से भी ज्यादा बुरी बंगाल की हालत : भाजपा

भाजपा ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान कानून व्यवस्था को वामपंथ के शासन के समय से भी बदतर बताया है। भाजपा का एक दल उत्तर 24 परगना में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले की स्थिति का जायजा लिया।

राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कोलकाता में पार्टी के चार वरिष्ठ

नेताओं के साथ संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ''पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था वाम शासन से भी ज्यादा बुरी हालात में है। जिस तरह से शासन द्वारा आधिकारिक मशीनरी का लोगों को डराने-धमकाने में प्रयोग किया जा रहा है, वह बहुत निंदनीय है।''

श्री नकवी ने कहा, ''हम यहां पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों का आकलन करने आए हैं और इस संबंध में एक रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेताओं को सौंपेंगे।''

पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष श्री राहुल सिन्हा ने बताया, ''भाजपा के दल ने उत्तर 24 परगना के संदेशखाली का दौरा किया और कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में संदेशखाली के हमलों में घायल हुए 30 पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की।'' उन्होंने कहा कि इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव संजय मित्रा से मुलाकात की। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में 28 मई को 30 भाजपा कार्यकर्ताओं पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। श्री नकवी के अलावा प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद श्री एस.एस. अहलूवालिया, पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी, पार्टी के राज्य प्रभारी श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, और आसनसोल से सांसद श्री बाबुल सुप्रियो शामिल थे।■

पश्चिम बंगाल में 'आप' खत्म

पूरी राज्य इकाई भाजपा में शामिल

इस बार के लोकसभा चुनाव में देश भर में भाजपा के पक्ष में चली लहर से पश्चिम बंगाल में पार्टी को मिली अच्छी सफलता के बाद आम आदमी पार्टी (आप) की पूरी प्रदेश इकाई भाजपा में शामिल हो गयी। आप नेता श्री अमित कुमार ने कहा कि राज्य में भाजपा ही एकमात्र मंच है जो जनता के लिए संघर्ष करेगा।

भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष श्री राहुल सिन्हा ने पत्रकारों से कहा कि बंगाल में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। हम आप कार्यकर्ताओं और नेताओं का हमारी पार्टी में शामिल होने का स्वागत करते है और ये सभी नेता और कार्यकर्ता अब भाजपा के लिए काम करेंगे।

पिछले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद आप ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की इकाई बनाई थी। आप ने बंगाल में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में चार सीटों पर चुनाव भी लड़ा था लेकिन उसके चारों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।

भाजपा में शामिल हुए आप के वरिष्ठ नेता श्री महमूद जाफरी ने कहा कि हम बिना किसी चाहत के आप में शामिल हुए थे, लेकिन हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं और यह मौका हमे इस पार्टी में रहकर नहीं मिला।

श्री राहुल सिन्हा ने बताया कि आम आदमी पार्टी की पूरी प्रदेश इकाई ने भाजपा में विलय का फैसला किया है और वे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि कांग्रेस, वाम दलों समेत अन्य दलों के अनेक नेता भी हमारे साथ संपर्क में हैं। ■